(Rs. in crore)

As on 31.3.91		As on 31.3.95	
HFC	FCI	HFC	FCI
652.10	390.02	1799.20	1123.82

Production of synthetic milk

504. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the milk and milk products order of the Government synthetic milk is being manufactured on large scale in various parts of the country endangering the health and lives of the consumers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures Government propose to take to ban the manufacture and supply of synthetic milk in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) to (c) The sale of milk and milk products containing a substance not found in milk is already prohibited under the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act—1955. The food (health) Authorities of States/Union Territories have been requested to keep a strict vigil on quality of milk.

Newspaper report on control of bulk drugs

505. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item in 'Financial Express' dated 12th February, 1996 captioned "Government Panel to review the control of 19 bulk drugs";

(b) if so, the names of the bulk drugs and the companies who have submitted representation for de-control of the same;

(c) the turnover of each bulk drug and the market share of the leader by March, 1990;

(d) since when each representation if pending; and

(e) whether it is mentioned in the Policy that transparency will be maintained alongwith basis and data on which each drug has been identified under Price Control, if so, by when such data will be made available?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) Representations were received from time to time subsequent to announcement of DPCO, 1995 on 6.1.1995 and a Committee has been constituted to look into the matter. Turnover data as collected and compiled by the Expert Group of the Standing Committee appointed to review the Drugs Policy, 1986, for the year 1989-90 and Retail Trade Data as available from ORG, March, 1990 has been utilised for the purpose of determining list of price controlled drugs by application of criteria laid down in 'Modifications in Drug Policy, 1986', across the board to have transparency and objectivity".

ग्रामीण विकास हेतु आंवटित धनराशि का उपयोग न किया जाना

506. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों द्वारा देश के ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये आवंटित वार्षिक बजट की राशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में आवंटित राशि का भरपूर उपयोग नहीं किया है;

(ग) उपरोक्त वर्षों में किन-किन राज्य सरकारों ने आवंटित बजट राशि का 50 प्रतिशत से कम उपयोग किया है;

(घ) क्या सरकार ने इस राशि के उपयोग न किये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में बेरोजगारी कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य में प्रतिवर्ष कितने-कितने प्रतिशत कमी आने का अनुमान है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख): जी हां। अनेक राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वार्षिक बजट की राशि का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रही हों। 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन की राशि का जो राज्य सरकारें पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी (890 प्रतिशत तक) उनको दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित निधियों का 90 प्रतिशत तक उपयोग न करने वाली राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र

वर्ष/योजनाएं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1992-93	
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	बिहार, गोवा, कर्नाटक
2. जवाहर रोजगार योजना	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	असम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर मेघालय, नागालैंड, पं बंगाल व दिल्ली
1993-94	
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्य क्रम	अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पं बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दमन व द्वीप तथा पांडिचेरी
2. जवाहर रोजगार योजना	हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, त्रिपुरा तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	अरूणाचल प्रदेश, बिहार गुजरात, केरल महाराष्ट्र, नागालैंड, पं बंगाल दादर व नगर हवेली, दिल्ली तथा पांडिचेरी
1994-95	
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पं बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दमन व द्वीव, पांडिचेरी

	2
2. जवाहर रोजगार योजना	केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा दादर नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, दादर व नागर हवेली

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1992-93 से 1994-95 तक आवंटित निधियों का 50 प्रतिशत से कम उपयोग करने वाले राज्यों को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:—

	1992-93	1993-94	1994-95
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	—	पं बंगाल	नागालैंड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह दमन व द्वीव
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	नागालैंड दिल्ली	नागालैंड, दादर व नगर हवेली	नागालैंड, दादर व नगर हवेली
जवाहर रोजगार योजना	मणिपुर मेघालय, दमन व द्वीव तथा पांडिचेरी	जम्मू व कश्मीर मणिपुर, मेघालय दमन व द्वीव और पांडिचेरी	मणिपुर, मेघालय, पंजाब, दमन व द्वीव तथा पांडिचेरी

(घ) और (ङ) मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियों के उपयोग न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी/वृद्धि कई बातों पर निर्भर करती है जैसे (1) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को पलायन, (2) मजदूरी रोजगार हेतु मांग, (3) कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर आदि। इसलिए आबंटित हुए संसाधनों के उपयोग न होने के कारण बेरोजगार लोगों की संख्या के बारे में अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

रसायनों और उर्वरकों का आयात

507. **श्री जनेश्वर मिश्र:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कितने रुपए मूल्य के उर्वरक व रसायन का आयात किया है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित उर्वरकों एवं रसायनों की मात्रा कितनी है;

(ग) उर्वरकों एवं रसायनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) और (ख) जहां तक उर्वरकों का संबंध है, देश में यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी तीन प्रमुख आयातित उर्वरक हैं। इनमें से केवल यूरिया ही सरकार के मूल्य और संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता है तथा इसका आयात सरणीबद्ध है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में यूरिया का आयात निम्न प्रकार है: